Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 136-2016/Ext] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 26, 2016 (BHADRA 4, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 26th August, 2016

No. 28-HLA of 2016/91.— The Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification)Amendment Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 28- HLA of 2016

THE HARYANA STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) AMENDMENT BILL, 2016.

A

BILL

further to amend the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2016.

Amendment of section 3 of Haryana Act 41 of 1974.

2. In sub-section (2) of section 3 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974.-

(i) in clause (c), for the sign " ." existing the end, the sign " ; " shall be substituted;

(ii) after clause (c), the following clauses shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 1st June, 1975 and the 14th June, 2016 respectively, namely:-

"(d) Leader of Opposition;

(e) Government Chief Whip.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present Section-3 of the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974 provides certain offices of profit not to disqualify the holder thereof for being elected as, or for being a member of the Legislature of the State of Haryana. The Office of Government Chief Whip and Leader of Opposition have not been included in the aforesaid Act and have been provided other facilities which are not applicable to the Members of Legislative Assembly.

In order to include the offices of Government Chief Whip and Leader of Opposition in the Act, clause (d) and (e) are proposed to be inserted in sub-section (2) of Section 3 by introducing a Bill.

RAM BILAS SHARMA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 26th August,2016.

R.K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed amendment of Leader of Opposition and Government Chief Whip of State will entail an extra expenditure approximately Rs.50,00,000/- (Rs. Fifty lakh only) per year from the State Exchequer.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 28-एच०एल०ए०

हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2016
हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2016 कहा जा सकता है ।

1974 के हरियाणा अधिनियम 41 की धारा 3 का संशोधन ।

2. हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (2) में,–

(i) खण्ड (ग) में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '';'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे तथा क्रमशः प्रथम जून, 1975 तथा 14 जून, 2016 से जोड़ दिए समझे जाएंगे, अर्थात्:–

''(घ) विपक्ष का नेता ;

(ङ) सरकारी मुख्य सचेतक।'' ।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा राज्य विधानमण्डल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 में कुछ कार्यालयों में लाभ के पद पर रहते हुए हरियाणा राज्य की विधान मण्डल का सदस्य निर्वाचित होने पर उसके धारक को अयोग्य घोषित नहीं होने देता। सरकारी मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के कार्यालयों को उक्त अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है व सुविधाएं जो विधान सभा के अन्य सदस्यों को प्राप्त हैं, उन्हें प्रदान की गई हैं।

सरकारी मुख्य सचेतक और विपक्ष के नेता के कार्यालयों को उक्त अधिनियम में शामिल करने के लिए धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (ङ) में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

राम बिलास शर्मा,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 26 अगस्त, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा विधान सभा के विपक्ष के नेता तथा सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्तावित संशोधन से राजकोष पर लगभग 50,00,000/– रु0 प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्चा आएगा ।

54591—H.V.S.—H.G.P.,Chd.